www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 329 | जौनपुर, सोमवार, 20 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

विवाद पर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी की निष्पक्ष और समय–सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, इस मामले से जुड़ी चार अलग–अलग याचिकाओं पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच सुनवाई करेगी। 13 जुलाई को कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई और मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। बेंच ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 13 जुलाई के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा चूंकि कुछ रिट याचिकाओं में यह कहा गया है कि कुछ थ्त पहले ही दर्ज हो चुकी हैं और मामले की जांच के लिए एक बनाई गई है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी को निर्देश देते हैं कि वह इस कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। याचिकाकर्ताओं में से एक, नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने इस मामले कीजांच की मांग की है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फाइनेंस की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ऑडिट कराने की भी मांग की हैय यह ट्रस्ट राम मंदिर के कामकाज को संभालता है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर एक और याचिका में मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और प्रशासन से जुड़ी।

अमृत भारत स्टेशन योजना का विस्तार, पनकी धाम रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित

कानपुर, (संवाददाता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित पनकी धाम रेलवे स्टेशन सहित देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस पनकी धाम स्टेशन अब धार्मिक पर्यटन और स्थानीय आवागमन को नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज मंडल के पनकी धाम, फतेहपुर और विंध्याचल स्टेशन सहित देश के 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन पनकी धाम स्टेशन परिसर में भी हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम की शुरुआत अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा) धनंजय कुमार सिंह और उप मुख्य यातायात प्रबंधक आकांशु गोविल ने अतिथियों के स्वागत से की। अधिकारियों ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध पुनर्विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ स्थानीय संस्कृति और विरासत को भी स्टेशन की पहचान का हिस्सा बनाना है।

निजी रॉकेट आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रमाण - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट, स्काईरूट एयरोस्पेस के श्विक्रम–1श के सफल लॉन्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट की पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक अहम पल है। उन्होंने श्एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी नए रास्ते खोल रही है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और बिना किसी डर के इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने 'स्काईरूट एयरोस्पेस' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पवन कुमार चांदना और सह–संस्थापक नागा भरत डाका से फोन पर बात कर शनिवार को हासिल इस उपलब्धि के लिए उन्हें और उनकी कंपनी को बधाई दी। 'स्काईरूट एयरोस्पेस' के दोनों वरिष्ठ अधिकारी प्रक्षेपण के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मिशन नियंत्रण केंद्र(एमसीसी) में मौजूद थे। मोदी ने उन्हें अपनी 'हार्दिक शुभकामनाएं' देते हुए कहा कि उनका आज का 'मिशन आगमन' आगे भी इसी तरह सफलता के साथ आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि यह मिशन साबित करता है कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं।' इस पर चांदना ने प्रधानमंत्री को बताया कि रॉकेट को पूरी तरह भारत में ही डिजाइन किया गया है और यहीं इसका निर्माण किया गया है। चांदना ने प्रधानमंत्री के उस पोस्टकार्ड का भी उल्लेख किया, जिस पर 'वंदे मातरम्' का संदेश अंकित था और उसे प्रक्षेपण यान 450 किलोमीटर दूर स्थिति पृथ्वी की निचली कक्षा तक लेकर गया। उन्होंने कहा कि आपक पोस्टकार्ड सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया है। 'वंदे मातरम्' अब पृथ्वी की कक्षा में है। इस मिशन का संचालन हैदराबाद से संचालित निजी कंपनी 'स्काईरूट एयरोस्पेस' ने किया। कंपनी ने इस मिशन को ''बड़ी सफलता'' करार दिया।

शाह के बंगाल दौरे पर ढाका–चीन की निगाहें, सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर मंथन

कोलकाता, (एजेंसी)।ढाका और बीजिंग के बदलते रणनीतिक समीकरणों तथा तीस्ता परियोजना में चीन की बढ़ती भूमिका के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर बंगाल दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की सामरिक जीवनरेखा कहे जाने वाले सिलिगुड़ी कॉरिडोर यानी श्चिकन नेकश की सुरक्षा को लेकर होने वाली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक पर जहां नई दिल्ली की पैनी नजर है, वहीं रणनीतिक और सुरक्षा हलकों के मुताबिक बांग्लादेश और चीन भी इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने उत्तर बंगाल में सैन्य तैयारियों, सुरक्षा स्थिति और परिचालन क्षमता की समीक्षा की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उत्तर बंगाल पहुंचकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी और देश के सबसे संवेदनशील रणनीतिक गलियारों में शामिल चिकन नेक की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन कर रहे हैं।

रक्षा विशेषज्ञ इसे गृह मंत्री के कार्यकाल में सिलिगुड़ी कॉरिडोर को लेकर अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षाओं में से एक मान रहे हैं। तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात बागडोगरा पहुंचे शाह का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा सिलिगुड़ी कॉरिडोर भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय संपर्क मार्ग है। पूर्वोत्तर के करीब 5.5 करोड़ लोगों की नागरिक आपूर्ति, सैन्य रसद, रेलवे नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग और व्यापारिक गतिविधियां इसी गलियारे पर निर्भर हैं।

ईसीआई की पहली अखिल भारतीय मीडिया कॉन्फ्रेंस, चुनावी प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका पर जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में "हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करनारू चुनावों में मीडिया की भूमिका" विषय पर पहली अखिल भारतीय मीडिया कॉन्फ्रेंस–2026 का आयोजन किया। सम्मेलन में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 380 से अधिक मीडिया पेशेवरों ने भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारक समवर्ती रूप से इसकी ऑडिट करते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 95 करोड़ मतदाताओं वाली भारत की मतदाता सूची एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ लगातार अद्यतन होती रहती है। उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और 15 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) इस प्रक्रिया में "समवर्ती लेखा परीक्षक" के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत भारतीय मतदाताओं के चुनावी व्यवस्था पर भरोसे और लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है।

ऑपरेशन सिंदूर भारत की विश्व स्तरीय रक्षा तैयारियों का प्रमाण – राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आधुनिक, सक्षम और मानकों के अनुरूप रक्षा तैयारियों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं, जिनके कारण यह क्षमता विकसित हुई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार का मजबूत तंत्र जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में स्टार्टअप, एमएसएमई और युवा नवाचारकर्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को करारा जवाब दिया, जिससे आतंकवाद के प्रति सरकार की श्जीरो टॉलरेंसश नीति स्पष्ट हुई। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की राष्ट्र प्रथम और सैन्य बल प्रथम की भावना को भी श्रेय दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंसश केवल एक बयान नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली है। उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ केवल अपनी सीमा पर ही नहीं, बल्कि जहां से आतंकवाद संचालित होता है, वहां तक पहुंचकर भी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि श्ऑपरेशन सिंदूरश जैसे जटिल अभियान की सफलता में भारत के बदले हुए रक्षा क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही। इसे उन्होंने तकनीक आधारित युद्ध का उत्कृष्ट उदाहरण और भारतीय उद्योगों पर सरकार के भरोसे का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, श्इस अभियान के दौरान आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ कई अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया।

माजबत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर सीएम हिमंता सरमा ने पीएम मोदी का जताया आभार

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित माजबत रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 117 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक स्टेशन का आधुनिकीकरण पूर्वोत्तर में रेलवे अवसंरचना को मजबूत करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि पुनर्विकसित माजबत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस ऐतिहासिक स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है। सरमा ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे असम में 50 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने इसे राज्य में रेलवे संपर्क और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उदलगुरी जिले में स्थित माजबत रेलवे स्टेशन की स्थापना वर्ष 1909 के आसपास ब्रिटिश काल में हुई थी। यह असम के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है और एक सदी से अधिक समय से क्षेत्र के प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। माजबत रेलवे स्टेशन ने उत्तरी असम के चाय उत्पादक क्षेत्रों को प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से चाय, लकड़ी, कृषि उत्पादों और यात्रियों की आवाजाही सुगम हुई। साथ ही इसने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों और देश के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क को भी मजबूत किया। पुनर्विकास के बाद स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं, बेहतर बुनियादी ढांचा और उन्नत सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाते हुए यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और स्थानीय स्थापत्य विशेषताओं को भी संरक्षित रखना है।

पीयूष गोयल ने फिनलैंड की प्रमुख कंपनियों से की मुलाकात, तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के साथ रणनीतिक बैठकों के जरिए भारत–फिनलैंड आर्थिक एवं तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। बैठकों में दूरसंचार, अनुसंधान, स्मार्ट अवसंरचना, उन्नत विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात कर अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों, 5जी और 6जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार साझेदारी पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका और उभरती डिजिटल तकनीकों में सहयोग के नए अवसरों पर भी विचार किया गया। यूरोप के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में शामिल वीटीटी तकनीकी अनुसंधान केंद्र में हुई बैठक के दौरान अनुसंधान, नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी, औद्योगिक परिवर्तन, उन्नत सामग्री, डिजिटलीकरण और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अनुसंधान साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करने की संभावनाओं पर भी विचार किया। केओएनई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में स्मार्ट शहरी अवसंरचना, लिफ्ट और एस्केलेटर तकनीक, सतत निर्माण समाधान, उन्नत विनिर्माण और स्थानीयकरण पर सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। भारत के तेजी से विकसित हो रहे अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी विचार हुआ। केम्पी समूह के नेतृत्व के साथ हुई।

आयुष्मान भारत की समीक्षा बैठक में क्लेम प्रबंधन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक (चिंतन शिविर) में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अगले चरण के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर केंद्र और राज्यों के साथ मंथन किया। बैठक में कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, क्लीनिकल गवर्नेंस, दावा प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर एनएचए की वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न परिचालन दिशानिर्देश भी जारी किए गए। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित बैठक का उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने किया। इस दौरान उन्होंने एनएचए की वार्षिक रिपोर्ट के साथ जिला कार्यान्वयन इकाई (डीआईयू), लाभार्थी सशक्तिकरण (बीई) और अस्पताल सूचीकरण मॉड्यूल (एचईएम) से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। इनका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी और मानकीकृत बनाना है। प्रतापराव जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आधुनिक चिकित्सा और आयुष दोनों को सशक्त बनाकर एक समेकित स्वास्थ्य इकोसिस्टम विकसित कर रही है। उन्होंने बताया कि एबी पीएम–जेएवाई के तहत अब तक 37,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से 1.91 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 94 करोड़ से अधिक आभा नंबर बनाए जा चुके हैं और 100 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जोड़े जा चुके हैं।

महार्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम में वाहन प्रवेश द्वार-1 पर नवीन सुरक्षा क्षेत्र एवं एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली का उद्घाटन

ब्यूरो चीफ
राजेश कुमार श्रीवास्तव

अयोध्या। महार्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम में आज वाहन प्रवेश द्वार–1 पर स्थापित नवीन सुरक्षा होल्डिंग क्षेत्र (एसएचए) एवं एक्स–रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएस) का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री अमित भट्ट तथा एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर कासो, सीआईएसएफ श्री रविंदर सिंह सहित भारतीय विमानपत्तान प्राधिकरण एवं सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वाहन प्रवेश द्वार–1 पर स्थापित अत्याधुनिक स्वदेशी एक्सबीआईएस मशीन के संचालन से हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। इस नई सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से वाहनों के माध्यम से आने वाली सामग्री की जांच अधिक प्रभावी, त्वरित एवं विश्वसनीय ढंग से की जा सकेगी, जिससे हवाई अड्डे की समग्र सुरक्षा संरचना को महत्वपूर्ण मजबूती प्राप्त होगी। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों एवं हवाई अड्डे की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वदेश में निर्मित इस ग्ठै मशीन की स्थापना श्आत्मनिर्भर भारतश के संकल्प को भी सुदृढ़ करती है तथा भविष्य में हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाएगी। महार्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों एवं उन्नत सुरक्षा उपायों को अपनाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

संपादकीय

कदम सही दिशा में

जिस देश में कार स्वामित्व कुल आबादी में आठ प्रतिशत से नीचे हो, वहां कार मालिकों को इतनी बड़ी सब्सिडी देना सिरे से काबिल–ए–एतराज है। इससे बेहतर नजरिया डीजल व पेट्रोल कार रखना महंगा बनाना होता। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति सही दिशा में पहल है। राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिहाज यह लाभदायक हो सकती है। लेकिन इस नीति का बोझ आम करदाताओं पर डालने पर नजरिया आपत्तिजनक है। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने के लिए 30 लाख रुपये तक की कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में सौ फीसदी छूट दी गई है। साथ ही प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए बीएस–4 या उससे पुराने चार पहिया वाहनों के लिए एक लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव दिया जाएगा। अगले चार वर्ष में दिल्ली सरकार 15,000 करोड़ रुपये ऐसी सब्सिडी और ईवी के चार्जिंग स्थल बनाने आदि पर खर्च करेगी। राजकोष से खर्च होने वाला ये पैसा उन नागरिकों की कीमत पर होगा, जो कार रखने का सपना भी नहीं देख पाते। जिस देश में कार स्वामित्व कुल आबादी में आठ प्रतिशत से नीचे हो, वहां कार मालिकों को ऐसी सब्सिडी देना सिरे से काबिल–ए–एतराज है। इससे बेहतर नजरिया डीजल व पेट्रोल कार रखना महंगा बनाना होता। यह फैसला लिया जा सकता था कि ऐसी कार रखने वालों को ईवी की तुलना में दो या तीन गुना अधिक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क देना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर वैसे वाहनों का पार्किंग शुल्क भी दो या तीन गुना ज्यादा किया जा सकता था। भारत में कार रखने वाले तबकों के लिए यह खर्च कोई बड़ा बोझ नहीं है। उस स्थिति में इस जरूरी पहल का बोझ राजकोष पर नहीं पड़ता। बल्कि सरकार अतिरिक्त राजस्व जुटा सकती थी, जिसे सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च किया जा सकता था। लेकिन अब अंदेशा है कि सार्वजनिक कल्याण और गरीब तबकों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए रखे जाने वाले बजट पर ईवी को प्राथमिकता देने के निर्णय की मार पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री–व्हिलर्स (ई–ऑटो) का पंजीकरण करने और एक अप्रैल 2028 से पेट्रोल–सीएनजी दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर केवल इलेक्ट्रिक मॉडल्स को अनुमति देने का फैसला किया है। ये कदम सही दिशा में हैं।

मंदिरों में भ्रष्टाचारः वहां सुशासन की नई क्रांति का सूत्रपात हो

ललित

भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक दर्शन से नहीं है, बल्कि उन मंदिरों से भी है जो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन का आधार हैं। अयोध्या का श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी, तिरुपति, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सालासर बालाजी, खाटू श्यामजी जैसे मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि यहां उन्हें केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और नैतिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। लेकिन जब इन्हीं मंदिरों से चढ़ावे की चोरी, वित्तीय अनियमितताओं, वीआईपी संस्कृति, पुजारियों अथवा कर्मचारियों के अनुचित आचरण और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आती हैं, तब केवल कोई संस्था बदनाम नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था घायल होती है। हाल के वर्षों में श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ और अब माता वैष्णोदेवी मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिरों की व्यवस्था को केवल धार्मिक भावना के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस धन को श्रद्धालु भगवान का अर्पण मानकर समर्पित करते हैं, वह किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं है। उस धन का प्रत्येक रुपया सार्वजनिक विश्वास की धरोहर है। यदि उसी में अपारदर्शिता या चोरी का संदेह पैदा हो जाए तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास के साथ विश्वासघात है। मंदिरों में बढ़ती अव्यवस्था का दूसरा गंभीर पक्ष है–वीआईपी दर्शन संस्कृति। आज देश का सामान्य श्रद्धालु कई–कई घंटे कतार में खड़ा रहता है। वृद्ध, महिलाएं, दिव्यांग और छोटे बच्चों के साथ आए परिवार कठिन परिस्थितियों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री, विधायक, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति पहुंचता है, सामान्य दर्शन रोक दिए जाते हैं और वीआईपी दर्शन शुरू हो जाते हैं। आम श्रद्धालु की लाइन रोक दी जाती है, उसके दर्शन का समय बाधित होता है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि भगवान के दरबार में भी सभी बराबर नहीं हैं। यह स्थिति भारतीय संस्कृति और धर्म की मूल भावना के विपरीत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के समक्ष राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। यदि मंदिरों में भी सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार का प्रदर्शन होगा तो यह धर्म के मूल स्वरूप का अपमान है। मंदिरों को लोकतांत्रिक समानता और आध्यात्मिक समरसता का सर्वोच्च उदाहरण बनना चाहिए, न कि सामाजिक असमानता का मंच। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में 'समान मन्दिर दर्शन नीति' लागू की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा या अत्यंत विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को सामान्य श्रद्धालुओं की कतार से अलग विशेष दर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो, तब भी आम श्रद्धालुओं के दर्शन बाधित नहीं होने चाहिए। भगवान के दरबार में सबसे बड़ा वीआईपी केवल श्रद्धा होनी चाहिए, पद और सत्ता नहीं। इसी प्रकार मंदिरों की चढ़ावा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आज डिजिटल भारत का युग है, फिर भी अनेक मंदिरों में दान और चढ़ावे की पारदर्शी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। प्रत्येक बड़े मंदिर में दान–पात्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, बारकोड आधारित सीलिंग, नियमित स्वतंत्र ऑडिट तथा प्रत्येक माह आय–व्यय का सार्वजनिक विवरण वेबसाइट और सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रद्धालु को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा दिया गया धन कहां और किस उद्देश्य में उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन में केवल धार्मिक पहचान ही नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को स्थान मिले जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कलंक हो, जिनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शी रहा हो और जिन पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या आपराधिक आरोप न हों। समय–समय पर उनके कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाए। मंदिर प्रबंधन किसी का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आचार–संहिता बनाई जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा, दलालों से मिलीभगत, नशाखोरी या किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई हो। सालासर बालाजी में बाउंसरों द्वारा श्रद्धालु की पिटाई और खाटू श्यामजी में मुख्य पुजारी से जुड़े विवाद जैसे प्रसंग यह संकेत देते हैं कि केवल धार्मिक पहचान पर्याप्त नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। मंदिरों में दलाल संस्कृति भी समाप्त की जानी चाहिए। दर्शन, प्रसाद, पूजा और विशेष अनुष्ठानों के नाम पर होने वाली अनधिकृत वसूली श्रद्धालुओं के विश्वास को कमजोर करती है। सभी सेवाओं की दरें सार्वजनिक हों, ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध हो और किसी भी अतिरिक्त वसूली पर कठोर दंड का प्रावधान हो। भारत आज विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया भर से करोड़ों लोग भारतीय मंदिरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। धार्मिक पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। ऐसे समय यदि मंदिरों की व्यवस्थाओं पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अव्यवस्था के आरोप लगते हैं तो केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की छवि प्रभावित होती है। विश्व यह संदेश ग्रहण करता है कि जिस देश ने धर्म और नैतिकता का संदेश दिया, वह अपने ही धर्मस्थलों को पारदर्शी नहीं बना पाया, वहां भी व्यापक भ्रष्टाचार पसरा है। भारत

सरकार और राज्य सरकारों को अब इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। 'राष्ट्रीय मंदिर सुशासन आयोग' जैसी स्वतंत्र संस्था का गठन किया जा सकता है, जो बड़े मंदिरों की वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही, दर्शन व्यवस्था और श्रद्धालुओं के अधिकारों की निगरानी करे। प्रत्येक मंदिर के लिए सेवा–मानक निर्धारित हों तथा शिकायत निवारण की समयबद्ध व्यवस्था हो। धार्मिक संगठनों और संत समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा–पाठ नहीं, बल्कि सत्य, ईमानदारी, सेवा और उत्तरदायित्व है। यदि मंदिरों के भीतर ही इन मूल्यों का ह्रास होगा तो समाज को नैतिक दिशा कौन देगा? मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के विद्यालय भी होने चाहिए। आज आवश्यकता किसी छोटे–मोटे सुधार की नहीं, बल्कि मंदिर प्रशासन में एक नैतिक क्रांति की है। यह क्रांति पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और सेवा के चार स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए। मंदिरों को तकनीक से जोड़ना होगा, वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और ऑडिट–आधारित बनाना होगा, वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना होगा तथा हर श्रद्धालु को समान सम्मान देना होगा। याद रखना होगा कि मंदिरों की सबसे बड़ी संपत्ति उनका स्वर्ण, रजत या चढ़ावा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का विश्वास है। यदि विश्वास टूट गया तो सबसे भव्य मंदिर भी अपनी आत्मा खो देगा। इसलिए समय की पुकार है कि मंदिरों को भ्रष्टाचार से मुक्त, दर्शन व्यवस्था को समान, प्रशासन को पारदर्शी और सेवा को मानवीय बनाया जाए। यही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, यही भारतीय संस्कृति का वास्तविक सम्मान होगा और यही वह परिवर्तन होगा जो भारत को केवल आध्यात्मिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि नैतिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा।

मानसून नहीं, शहरों की व्यवस्था समस्या

राजेंद्र

दिल्ली–एनसीआर में हाल ही में हुई सड़क धंसने की घटनाएं इसी उपेक्षा का परिणाम हैं। सड़कें किसी एक बारिश से नहीं धंसतीं। ऐसी घटनाएं आमतौर पर वर्षों से पाइपलाइन रिसाव, ठीक से न दबाई गई मिट्टी, पुराने उपयोगिता नेटवर्क, अपर्याप्त जल निकासी या बार–बार खुदाई के बाद उचित पुनर्स्थापन न होने के कारण सतह के नीचे जमा होती कमजोरियों का परिणाम होती हैं। हर मानसून में भारत के शहर एक जैसी कहानी दोहराते हैं। तेज बारिश की पहली बौछार पड़ते ही सड़कें पानी में डूब जाती हैं, लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, वाहन खराब हो जाते हैं और सोशल मीडिया जलमग्न सड़कों, उफनती नालियों तथा धंसती सड़कों की तस्वीरों से भर जाता है। पानी उतरने के बाद सरकारें जांच के आदेश देती हैं, संबंधित एजेंसियां सुधार के वादे करती हैं और अस्थायी मरम्मत शुरू हो जाती है, लेकिन अगले मानसून तक वही स्थिति फिर सामने आ जाती है।हाल ही में दिल्ली–एनसीआर (नेशनल केपिटल रीजन) में हुई भारी वर्षा ने एक बार फिर भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। दिल्ली में प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ और अनेक रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। गुरुग्राम– जो वर्षों से मानसून के दौरान जलभराव के लिए कुख्यात रहा है–में दिल्ली–गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, हीरो होंडा चौक और सोहना रोड जैसे प्रमुख मार्ग पानी में डूब गए, जिससे देश के प्रमुख कॉर्पोरेट केंद्रों में से एक लगभग ठहर गया।नोएडा में अंडरपास जलमग्न हो गए, नालियां उफनने लगीं और भीषण जाम लग गया। वहीं गाजियाबाद और फरीदाबाद में कई कॉलोनियां पानी में डूब गईं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और लोगों की आवाजाही बुरी तरह बाधित हुई। एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश के बाद सड़कें धंस गईं, जिसने केवल निर्माण की खामियों को ही नहीं, बल्कि शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग और रखरखाव की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को भी उजागर कर दिया। ये बार–बार होने वाली विफलताएं केवल असामान्य रूप से अधिक वर्षा का परिणाम नहीं हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि भारतीय शहरों की योजना, शासन व्यवस्था, वित्तपोषण और रखरखाव की पूरी प्रणाली में गंभीर संरचनात्मक कमियां मौजूद हैं। अब बहस इस बात पर नहीं रह गई है कि जलवायु परिवर्तन अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा रहा है या नहीं– यह निर्विवाद सत्य है। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हमारे शहर इस नई जलवायु वास्तविकता के अनुरूप स्वयं को पर्याप्त गति से ढाल पा रहे हैं? उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है।भारत के अधिकांश शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण उन ऐतिहासिक वर्षा पैटर्न के आधार पर किया गया था, जो आज की जलवायु परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। दूसरी ओर, तीव्र शहरीकरण ने मिट्टी और हरित क्षेत्रों की जगह कांक्रीट बिछा दिया है, जिससे भूजल का पुनर्भरण कम हुआ है और वर्षा जल का बहाव कई गुना बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में झीलें, आर्द्रभूमियां, गांवों के तालाब और प्राकृतिक जल–निकासी मार्ग या तो अंधाधुंध शहरी विस्तार की भेंट चढ़ गए हैं या फिर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि वे अपना प्राकृतिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो पानी पहले प्राकृतिक रूप से बाढ़ क्षेत्रों में फैल जाता था, वह अब घनी आबादी वाले कांक्रीट के जंगलों में फंस जाता है। नतीजा स्पष्ट है– जब भारी बारिश होती है तो पानी के निकलने के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर भी केवल जलवायु परिवर्तन यह नहीं समझा सकता कि हर वर्ष वही दृश्य क्यों दोहराए जाते हैं। इसके लिए शासन व्यवस्था की विफलताएं भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।एनसीआर संस्थागत विखंडन का एक स्पष्ट उदाहरण है। केवल दिल्ली में ही नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली जल बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा कई अन्य एजेंसियां शहरी बुनियादी ढांचे के अलग–अलग हिस्सों की जिम्मेदारी संभालती हैं। दिल्ली के बाहर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद अलग–अलग नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन वर्षा का पानी प्रशासनिक सीमाओं को नहीं पहचानता।इसके परिणाम हर जगह दिखाई देते हैं। सड़कों का पुनर्निर्माण भूमिगत उपयोगिताओं के साथ समन्वय किए बिना कर दिया जाता है। नालियां आगे के बड़े जल निकासी नेटवर्क से जुड़े बिना ही समाप्त हो जाती हैं। बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं व्यापक जल–विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) अध्ययन के बिना शुरू कर दी जाती हैं। रखरखाव की जिम्मेदारियां कई एजेंसियों में बंटी होने के कारण बाढ़ आने पर जवाबदेही भी बिखर जाती है। भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी उसका रखरखाव है। राजनीतिक प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, मेट्रो विस्तार और स्मार्ट सिटी जैसी दिखाई देने वाली परियोजनाओं पर केंद्रित रहती हैं। इसके विपरीत मानसून से पहले नालों की सफाई, रिटेनिंग वॉल की जांच, पुलियों की मरम्मत, भूमिगत उपयोगिताओं का मानचित्रण और पुराने हो चुके बुनियादी ढांचे की नियमित निगरानी जैसे कम आकर्षक लेकिन अत्यंत आवश्यक कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। दिल्ली–एनसीआर में हाल ही में हुई सड़क धंसने की घटनाएं इसी उपेक्षा का परिणाम हैं। सड़कें किसी एक बारिश से नहीं धंसतीं। ऐसी घटनाएं आमतौर पर वर्षों से पाइपलाइन रिसाव, ठीक से न दबाई गई मिट्टी, पुराने उपयोगिता नेटवर्क, अपर्याप्त जल निकासी या बार–बार खुदाई के बाद उचित पुनर्स्थापन न होने के कारण सतह के नीचे जमा होती कमजोरियों का परिणाम होती हैं। भारी बारिश केवल उन कमजोरियों को उजागर कर देती है जो लंबे समय से विकसित होती रही हैं। इसलिए श्जलवायु अनुकूलताा (क्लाइमेट रेजिलिएंस) को केवल पर्यावरणीय चिंता के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसे शहरी बुनियादी ढांचे की योजना का केंद्रीय सिद्धांत बनाना होगा। राजनीतिक विश्लेषण इस परिवर्तन में प्रकृति–आधारित समाधानों को कहीं अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

अकादमिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और कर्मचारी हितों के साथ आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

विष्णु प्रसाद

किसी भी राज्य की प्रगति का वास्तविक पैमाना उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है और इसकी गुणवत्ता केंद्र में खड़े शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों की सक्षमता, सुरक्षा और सम्मान पर निर्भर करती है। जब उच्च शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत मानव संसाधन को पदोन्नति, सेवा सुरक्षा, वित्तीय सम्मान और शोध के अवसर एक साथ मिलते हैं, तब शिक्षा राज्य के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की सबसे मजबूत धुरी बन जाती है। छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग इन दिनों इसी व्यापक और समग्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को केवल भवनों, पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं तक सीमित न रखकर उसे अकादमिक गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता, रोजगार सृजन, शोध संवर्धन और कर्मचारी कल्याण से जोड़ा है। हाल के महीनों में लिए गए निर्णय इस बात के प्रमाण हैं कि सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों को भविष्य के ज्ञान–केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पदोन्नतियों की लंबित फाइलों को गति देना, नई भर्तियां, वेतनमान व एरियर्स का निराकरण, तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति, शोध को प्रोत्साहन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे कदमों से विभाग ने हर मोर्चे पर ठोस और संवेदनशील पहल की है। पदोन्नति से संस्थागत नेतृत्व को नई शक्ति उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का एक बड़ा आधार उनका नेतृत्व होता है। जब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग्य और अनुभवी शिक्षकों को समय पर पदोन्नति मिलती है, तो उसका सीधा असर संस्थान की कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक क्षमता पर दिखाई देता है। लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं को गति देकर राज्य सरकार ने एक निर्णायक पहल की है। वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 362 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत कर प्राध्यापक (प्रोफेसर) बनाया गया है। इसके साथ ही 152 पदोन्नत प्राध्यापकों को स्नातक प्राचार्य तथा 07 स्नातक प्राचार्यों को स्नातकोत्तर (क्कत्र) प्राचार्य के पद पर पदोंन्नत किया गया है। इन निर्णयों से महाविद्यालयों की कमान अनुभवी हाथों में पहुँची है, जिससे संस्थागत निर्णय क्षमता, शैक्षणिक अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के लिए संस्थानों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक और विशेषज्ञ अनिवार्य हैं। राज्य सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश के बड़े अवसर निर्मित किए हैं। शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 595 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, विभागीय संरचना को सशक्त बनाने के लिए कुल 700 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। इनमें 625 पद सहायक प्राध्यापक, 50 पद ग्रंथपाल और 25 पद क्रीड़ाधिकारी के शामिल हैं। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से विषयवार अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर होगी, ग्रंथपालों से पुस्तकालय अकादमिक संसाधनों के प्रभावी केंद्र बनेंगे और क्रीड़ाधिकारियों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा। यह अभियान प्रदेश के योग्य युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। राज्य में सहायक प्राध्यापक बनने की आकांक्षा रखने वाले हजारों युवाओं के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (ष्टत्र–स्श्वत्र्ज) एक महत्वपूर्ण अवसर है। विभाग द्वारा ष्टत्र–स्श्वत्र्ज का आयोजन 04 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है द्य सरकार नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को अकादमिक करियर में आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक परिदृश्य और ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाने का अवसर देती है। प्रयोगशालाओं और तकनीकी तंत्र को मिला नया आधार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विषयों के लिए प्रयोगशालाएं, उपकरण और प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ उतने ही आवश्यक हैं जितने कक्षा और कक्ष। वर्ष 2025–26 के दौरान प्रयोगशाला तकनीशियन के 260 रिक्त पदों के विरुद्ध 247 अभ्यर्थियों तथा प्रयोगशाला परिचारक के 429 रिक्त पदों के विरुद्ध 399 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता से प्रयोगशालाओं का नियमित संचालन और विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। विभागीय मजबूती का सबसे बड़ा आधार कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यायपूर्ण वेतन संरचना और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान है। आपातकालीन रूप से अचयनित रहे 72 सहायक प्राध्यापकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठ, प्रवर श्रेणी और पे–बैंड–4 की स्वीकृति देकर 37.23 करोड़ रुपये की एरियर्स राशि उनके खातों में अंतरित की गई है, जो संस्थागत न्याय का प्रतीक है। इसी तरह, वर्ष 2021 और 2022 में नियुक्त लगभग 1168 सहायक प्राध्यापकों में से रिकॉर्ड 935 नवनियुक्त प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

अफसरशाही की जवाबदेही तय करना जरूरी

जगदीश

भ्रष्टाचार, आचार संहिता के उल्लंघन और पारदर्शिता कम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ–साथ इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि दिखावे या ग्लैमर की बजाय सेवा–भाव को प्राथमिकता दी जाए। खासकर जनता से सीधे जुड़े कामों में अधिकारियों को नागरिकों की कमेटियों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ध्जिला पुलिस प्रमुख के एक वीडियो के सामने आने के बाद दलितों का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। इस वीडियो में वे पुलिस वैन में एक वकील और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए दिख रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी एक 20 साल की लड़की की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी अविनाश पांडे की यह शर्मनाक और आपराधिक हरकत दिखाती है कि भारत की प्रमुख प्रशासनिक सेवाएं कई स्तरों पर देश को निराश कर रही हैं। वैसे यह कोई अकेली घटना नहीं है जो प्रशासन की सड़ी–गली, बदसलूकी वाली और जमीनी हकीकत से कटी हुई कार्यशैली को दिखाती हो। समय–समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो प्रशासनिक सेवाओं के शीर्ष स्तर को एक ऐसे खास वर्ग के रूप में दिखाती हैं जिसने सत्ता के दुरुपयोग और सरकारी तंत्र के शोषण को सामान्य मान लिया है।मेरठ का मामला यह सवाल खड़ा करता है कि ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर कैसे रखा गया और फिर उसे मेडल और अहम जिम्मेदारी कैसे दी गई? हमें ऐसे मामलों में मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण पर तो सवाल उठाने ही चाहिए, साथ ही वरिष्ठ अफसरों की भर्ती, नियुक्ति, प्रमोशन और सुपरविजन की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाने चाहिए। देश को उन धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए जिन्होंने सिविल सर्विस को श्शासन का स्टील फ्रेमश और इसकी 100 साल पुरानी भर्ती करने वाली संस्था– संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) को इसका श्संरक्षकश मानने की सोच को मजबूत किया है।एक जटिल और लंबे समय से चल रहे सिस्टम को बदलना मुश्किलों भरा काम है। खासकर जब ब्यूरोक्रेसी के राजनीतिकरण को लेकर नई चिंताएं हों। ये चिंताएं श्लेटरल एंट्रीश व्यवस्था पर हुई बहस में साफ दिखीं। सरकार ने 2024 में इसकी घोषणा की थी परन्तु बाद में आरक्षण कोटे को दरकिनार करने पर हुए जायज हंगामे के कारण इसे वापस ले लिया गया। यह एक अमेरिकी मॉडल है जिसमें चुनाव जीतने वाला नेता प्रशासन में अपने समर्थकों को नियुक्त करता है। कहा जा रहा है कि एक नई लेटरल एंट्री पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसे आरक्षण की रक्षा करनी होगी और तथाकथित श्स्पॉइल्स सिस्टमश के जाल में फंसने से बचना होगा।श्लेटरल एंट्रीश केंद्र सरकार की एक विशेष भर्ती प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र और गैर–सरकारी विशेषज्ञों को बिना पारंपरिक यूपीएससी परीक्षा दिए सीधे सरकारी विभागों में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसके तहत मुख्य रूप से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप–सचिव जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर भर्तियां की जाती हैं। जाहिर है, भारत राजनीतिक ब्यूरोक्रेसी का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि कुछ लोग तर्क देंगे कि हाल के वर्षों में अहम पदों का पहले ही काफी हद तक राजनीतिकरण हो चुका है।इन सब बातों को देखते हुए सुधारों पर एक व्यापक राजनीतिक सहमति अभी भी बन सकती है। एक तरफ तो सावधानी से बनाई गई नीति के जरिए नए सदस्यों को सीधे भर्ती (लेटरल एंट्री)करना एक तरीका है वहीं दूसरी तरफ सिस्टम में मौजूद उन लोगों को हटाना भी उतना ही जरूरी है जिन्होंने साफ तौर पर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है– जैसा कि मेरठ का मामला जो इन दिनों सुर्खियों में है। आज प्रशासन के ऊपरी स्तर का मतलब है लगभग असीमित शक्तियों वाले एक क्लब की स्थायी सदस्यता। हालांकि 2014 से भ्रष्टाचार के आरोप में लगभग 400 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। यह फरवरी 2026 तक कुल 10,171आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या का 4 प्रतिशत से भी कम है। ज्यादातर अधिकारी रिटायरमेंट तक नौकरी करते रहते हैं जो कि गैर–सरकारी क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। शक्तिशाली पदों पर कम निगरानी के साथ लगातार नौकरी मिलने का वादा गलत तरह के उम्मीदवारों को आकर्षित करता है और उन्हें बनाए रखता हैय ये ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो जोखिम नहीं लेना चाहते और बदलते दौर में जहां नए विचारों और इनपुट की जरूरत है– जीवन भर की सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। यूपीएससी के माध्यम से शीर्ष स्तर पर होने वाली भर्तियों के लिए जीवन भर की नौकरी (स्थायी सेवा) की पेशकश करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें पदोन्नति राजनीतिक दबावों से पूरी तरह सुरक्षित होती है। ठीक उसी तरह और उसी सीमा तक जैसा कि वर्तमान भर्ती प्रणाली में है। श्अग्निवीरश से प्रेरित एक ऐसा ढांचा जो शुरुआती नियुक्तियों को एक निश्चित अल्पकालिक कार्यकाल तक सीमित करता है और सेवा विस्तार के लिए मध्य–कैरियर में कड़े मूल्यांकन का प्रावधान करता है, सीमा पर तैनात सैनिकों की तुलना में वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए कहीं अधिक आवश्यक है। इसे श्स्पॉइल्स सिस्टमश (यानी राजनीतिक वफादारी के आधार पर नियुक्तियां और पदोन्नति) में बदलने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा मानकों के साथ, स्वतंत्र और वैधानिक सार्वजनिक पैनलों की देखरेख में एक पारदर्शी, प्रदर्शन पर आधारित प्रतिधारण (सेवा में बनाए रखने की) प्रणाली को तैयार करना संभव होना चाहिए। यह दृष्टिकोण लेटरल एंट्री के साथ मिलकर खाली पदों को भरने और व्यापक अनुभवों वाले लोगों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने का काम कर सकता है। लेटरल एंट्री के कारण यह व्यवस्था को उसकी श्रिप वैन विंकलश जैसी गहरी नींद और शिथिलता से झकझोर कर बाहर ला सकती है जिसमें वह डूब चुकी है। भारत को अपनी नौकरशाही का ग्लैमर भी कम करना चाहिए। नौकरशाह बहुत बड़े–बड़े कार्यालयों में बैठते हैं, उन्हें आलीशान घर मिलते हैं, वे बड़ी–बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बड़ी संख्या में सपोर्ट स्टाफ व पर्सनल असिस्टेंट मिलते हैं जो निजी नौकरों और सहायकों की तरह काम करते हैं। दुनिया भर में राजनीतिक नेता अपना बैग खुद उठाते हैं। यहां नौकरशाहों के जूते पॉलिश करने के लिए भी नौकर होते हैं। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। कर्नाटक के डीजीपी डॉ. एमए सलीम की हाल ही में तारीफ हुई थी क्योंकि उन्होंने सीनियर अधिकारियों के घरों पर निजी काम में लगे लगभग 3,000 कर्मचारियों को वापस मुख्य पुलिसिंग के काम में लगा दिया था। दुर्भाग्य से ऐसे कदम बहुत कम उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार, आचार संहिता के उल्लंघन और पारदर्शिता कम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ–साथ इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि दिखावे या ग्लैमर की बजाय सेवा–भाव को प्राथमिकता दी जाए। खासकर जनता से सीधे जुड़े कामों में अधिकारियों को नागरिकों की कमेटियों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाना चाहिए ।

वर्षों से अटकी सड़क पर आखिरकार पड़ी विधायक नीरज बोरा की नजर, किया सड़क व नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। फैजुल्लागंज वार्ड द्वितीय के अंतर्गत केशव नगर पश्चिम के निवासियों को जल्द ही जर्जर सड़क और जलभराव से निजात मिलेगी। मंजू सिंह के मकान से श्रीवास्तव जी के मकान तक सी. सी. सड़क और नाली का निर्माण कार्य होगा। रविवार को क्षेत्रीय विधायक डा. नीरज बोरा ने मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत होने वाले इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सड़क और नाली का निर्माण कार्य होने से स्थानीय निवासियों का आवागमन सुलभ होगा और जलभराव की समस्या भी नहीं होगी।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक पिछले काफी वर्षों से सड़क कच्ची होने और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने सड़क व नाली का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए विधायक डा. नीरज बोरा का आभार जताया। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि अंकुश बाजपेई, मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र मौर्या, सुनील सिंह, सतीश वर्मा, पवन शर्मा, आसिफ खान, गुलाम रब्बानी, अनिल कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, नसीम अख्तर, संतोष राय, ज्ञान चंद्र दीक्षित, शब्बीरुल हसन, अब्दुल गफ्फार सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे।

फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, होमगार्ड समेत चार गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने फर्जी आयकर अधिकारी बनकर व्यापारियों को निशाना बनाने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमवार शाम मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से व्यापारी की लाइसेंसी रिवॉल्वर, घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन, बड़ी संख्या में फर्जी आयकर विभाग के पहचान पत्र तथा अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

एसपी ग्रामीण ने बताया कि गिरोह के सदस्य स्वयं को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर व्यापारियों की दुकानों पर फर्जी छापेमारी करते थे। छापे का भय दिखाकर व्यापारी को डराते और फिर नकदी व कीमती सामान लूटने का प्रयास करते थे। रविवार को रामपुर थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी बरनवाल की दुकान पर भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने व्यापारी की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जबरन अपने कब्जे में ले ली थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों में जलालपुर निवासी रोशन तिवारी शामिल है, जो घर पर रहकर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा था। दूसरा आरोपी मुंगराबादशाहपुर निवासी अजय पटेल है, जो चालक का कार्य करता है। तीसरा आरोपी दिलीप कुमार मूल रूप से वाराणसी का निवासी है और वर्तमान में मुंगराबादशाहपुर में किराए पर रहकर श्मॉ अम्बे होंडा मोटर्स्श में कार्यरत है। चौथा आरोपी सिकरारा निवासी राजेश कुमार उपाध्याय है, जो जौनपुर पुलिस की पीआरवी–8545 पर होमगार्ड के पद पर तैनात है। वहीं सिकरारा निवासी जितेंद्र सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 से 35 फर्जी आयकर विभाग के पहचान पत्र, बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी कब्जे में ले लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वाहन सूर्य प्रकाश पटेल का है, जिसे तीसरे व्यक्ति के माध्यम से किराए पर लिया गया था।

पुलिस को आशंका है कि गिरोह पहले भी इसी तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनके संभावित नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। थाना रामपुर में सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है।

जौनपुर पुलिस ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर जांच या छापेमारी करने पहुंचे तो उसकी पहचान और अधिकृत दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग, एआईएमआईएम ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने के प्रस्तावित आदेश के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष इमरान बंटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर योगिता सिंह को सौंपते हुए कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष इमरान बंटी ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय केवल भवनों का समूह नहीं, बल्कि हजारों छात्र–छात्राओं के भविष्य और उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण से सबसे अधिक नुकसान उन विद्यार्थियों को होगा, जिनका किसी भी प्रशासनिक, कानूनी या राजनीतिक विवाद से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित कोई वैधानिक या प्रशासनिक विवाद है, तो उसका समाधान कानून के दायरे में निष्पक्ष, न्यायसंगत और मानवीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था बाधित हो और विद्यार्थियों का भविष्य संकट में पड़ जाए।

ज्ञापन के माध्यम से एआईएम आईएम ने मांग की कि जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए।

संगठन ने यह भी मांग की कि अंतिम न्यायिक एवं विधिक प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई स्थगित रखी जाए। साथ ही हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

एआईएमआईएम ने राष्ट्रपति से शिक्षा के अधिकार, संविधान की भावना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे कानून का सम्मान भी बना रहे और विद्यार्थियों का भविष्य भी सुरक्षित रह सके।

अब एलडीए के भूखंड, दुकान और फ्लैट का पंजीकरण कराने के लिए बैंक से मिलेगा लोन

लखनऊ, (संवाददाता)। एलडीए ने भूखंड या फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब पंजीकरण धनराशि के लिए भी बैंक लोन मिलेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की पहल पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पहले आओ–पहले पाओ योजना में फ्लैट खरीदने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होता है। सामान्य श्रेणी के आवेदक को अनुमानित मूल्य का पांच फीसदी और आरक्षित श्रेणी को 2.5 फीसदी पंजीकरण शुल्क देना होता है। ई–ऑक्शन में व्यावसायिक या आवासीय संपत्ति के लिए 10 फीसदी ईएमडी जमा करनी पड़ती है। लॉटरी से आवंटित होने वाले भूखंड और फ्लैट के लिए भी पंजीकरण धनराशि आवश्यक होती है। पहले बैंक केवल संपत्ति आवंटन के बाद ही ऋण देते थे। इससे कई लोग पंजीकरण शुल्क न होने के कारण आवेदन नहीं कर पाते थे। नई व्यवस्था से इच्छुक नागरिक आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे। एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आवंटन होने पर शेष धनराशि के लिए ऋण प्रक्रिया सरल होगी। आवेदक को दोबारा विस्तृत कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। यदि संपत्ति का आवंटन नहीं होता है, तो एलडीए पंजीकरण धनराशि सीधे बैंक को वापस कर देगा।

ध्वस्तीकरण आदेश न मिलने से नाराज वकीलों का एलडीए कार्यालय में हंगामा

लखनऊ, (संवाददाता)। अलीगंज अग्निकांड वाली बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश एलडीए ने 10 जून को जारी किया था। बिल्डिंग पर उसे चस्पा भी किया गया था, लेकिन बिल्डिंग मालिक के वकीलों ने आदेश की प्रति न मिलने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एलडीए के लालबाग स्थित विहित प्राधिकारी कार्यालय में हंगामा किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में वकील आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें आदेश की प्रति मांगने के बाद भी नहीं दी जा रही है। इसके लिए वह कई दिन से दौड़ रहे हैं। वकीलों ने चेतावनी भी दी कि यदि आदेश नहीं दिया गया तो वह शनिवार को एलडीए के गोमतीनगर कार्यालय में जाकर विरोध जताएंगे। इसकी वजह यह है कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही बिल्डिंग मालिक एलडीए के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के यहां अपील कर सकता है।

समय से पूर्व जन्मी 480 ग्राम की नवजात को 84 दिन के उपचार से मिला नया जीवन

लखनऊ, (संवाददाता)। निजी अस्पताल ने समय से पूर्व प्रसव (प्रीमैच्योर) वाले नवजात शिशु की चिकित्सा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था में जन्मी मात्र 480 ग्राम वजन की बच्ची को 84 दिनों के उपचार के बाद नया जीवन दिया है। वरिष्ठ नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. आशुतोष वर्मा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने यह सफलता हासिल की। जन्म के समय बच्ची की स्थिति बेहद गंभीर थी। उसे तत्काल नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती किया गया। इस दौरान बच्ची को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।

नीट यूजी 2026 में लखनऊ के श्रीनारायण हरि मिश्रा बने सिटी टॉपर

लखनऊ, (संवाददाता)। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के घोषित परिणामों में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के लखनऊ केंद्र के छात्र श्रीनारायण हरि मिश्रा ने ऑल इंडिया रैंक 105 प्राप्त कर लखनऊ सिटी टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। संस्थान ने इसे छात्र की मेहनत, अनुशासित तैयारी और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया है।आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के क्षेत्रीय निदेशक धनंजय कुमार मिश्रा ने श्रीनारायण की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे आकाश परिवार के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि श्रीनारायण ने अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने छात्र और उसके परिवार को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।श्रीनारायण हरि मिश्रा ने अपनी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऑल इंडिया रैंक 105 प्राप्त करना और लखनऊ का सिटी टॉपर बनना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है।

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत एवं लखनऊ जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राष्ट्र प्रथम की भावना को हमेशा आदर देने वाले अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बीर बहादुर भूतपूर्व सैनिकों का आज की इस पूर्व निर्धारित अवधप्रान्त एवं लखनऊ जिला की कार्य कारिणी की सम्मिलित मीटिंग में ह्रदय से आभार एवं स्वागत. मीटिंग की अध्यक्षता अवधप्रान्त अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल बीरेंद्र सिंह तोमर द्वारा की गई एवं संचालन लखनऊ जिला अध्यक्ष वारंट ऑफिसर ललित मोहन पंत द्वारा किया गया. सर्व प्रथम श्री पंत द्वारा उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का परिचय एवं स्वागत किया गया तत्पश्चात श्री पंत द्वारा संगठन गीत गाया गया जिसका गगन भेदी स्वरों में सभी महानुभावों ने जोशीले अंदाज में अनुसरण किया.इसके पश्चात् अवधप्रान्त अध्यक्ष श्रीमान तोमर साहब ने संगठन के गौरवशाली इतिहास, इसके कार्यक्रमों एवं इससे जुड़े देश के महान विभूतियों के बारे में बताया सभी को बताया जिसका सभी उपस्थित सदस्यों ने जोरदार तारीके से स्वागत किया. कारगिल विजयदिवस जो 26 जुलाई को हमारे संगठन द्वारा बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता रहा है, इस बार उसमें कुछ बदलाव सर्वासम्मति से किया जा रहा है. इस बार कारगिल विजय दिवस मनाने के लिये लखनऊ में निवास कर रहे संगठन के सदस्यों से अनुरोध है कि वे सेंट्रल कमांड विजय दिवस समारोह में शामिल हो जायँ या लखनऊ में अन्य जगह हो रहे समारोह में भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि हमारे संगठन की भव्यता, दिव्यता, एवं इसकी राष्ट्रप्रथम की सोच व विश्वसनीयता को देखते हुऐ जैसा ज्ञात हुआ है कि हमारे लखनऊ की महापौर महोदया एवं उत्तरप्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संगठन से संवाद करना चाहते हैं जिसके लिये अब आगामी महीनों में इस कार्यक्रम को उनकी सुविधानुसार सम्पन्न कराया जा सकता है.इसी क्रम में लखनऊ जिला अध्यक्ष श्री ललित मोहन पंत ने संगठन के महत्वता, एकता के बारे में बताया. अवधप्रान्त महासचिव सूबेदार मेजर बी एल वर्मा जी, लखनऊ जिला सहसचिव सी पी ओ घनश्याम केसरीजी, लखनऊ जिला सहसचिव वारंट ऑफिसर पूरन सिंह बोहरा जी, अवधप्रान्त कोषाध्यक्ष नायब सूबेदार अशोक कुमार पाण्डेय जी,लेफ्टिनेंट विमल प्रसाद जी, लेफ्टिनेंट अनिल कुमार सिंह जी, सूबेदारमेजर वाई. के. यादव जी, कैप्टन वी के सिंह जी एवं कमांडर वी. के सिंह जी द्वारा भी अपने अपने अमूल्य विचार सुझाव दिये गये जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया. लखनऊ जिले की नये साल के लिये मनोनीत कार्यकारिणि को भी इस मीटिंग में अवधप्रान्त महासचिव श्रीमान बी एल वर्मा साहब एवं अवधप्रान्त अध्यक्ष श्रीमान तोमर साहब के सम्मुख विचारार्थ रख्खा गया जिसका फाइनल अप्रूवल अवधप्रान्त की ।ळड में होगा ऐसा निर्णय हुआ.हमारे इस विशाल संगठन में विस्वास जताते हुऐ 5 नये निम्न सदस्य कल की मीटिंग में जुड़े हैं जिनका सम्मान कर्नल तोमर, सूबेदार मेजर बी एल वर्मा एवं वारंट ऑफिसर पंत,सी पी ओ घनश्याम केसरी, वारंट ऑफिसर पूरन सिंह एवं सूबेदार रतन सिंह अध्यक्ष पूर्वी भाग व अन्य सदस्यों ने किया।

1.नायक कुंदन सिंह मोबाइल 8756374876

2.कमांडर विजय कुमार सिंह, मोबाइल 9440937251

3.सूबेदार गोपाल सिंह, मोबाइल 9653075205

4.नायक बचन सिंह, मोबाइल 6386995799

5.हवालदार बी. बी. चंद, मोबाइल 9838556776

अंत में शांतिपाठ के साथ मीटिंग का समापन हुआ एवं उपस्थित सभी सदस्यों ने जलपान का लुत्फ लिया जिसका शानदार प्रबंध श्रीमान अशोक कुमार सिंह साहब ने किया था. आज के इस कार्यक्रम की सुन्दर व्यवस्था एवं जलपान आदि के उत्तम प्रबंध के लिये श्रीमान अशोक कुमार सिंह जी की सभी ने दिल खोलकर प्रशंसा की. आज के हमारे इस कार्यक्रम में संघ की शाखा से जुड़े आरएसएस कार्यकर्ता श्रीमान आमोद कुमार झा जी एवं समाजसेवी श्रीमान राम दयाल तिवारी जी एवं श्रीमान बल बहादुर सिंह जी धर्म जागरण प्रमुख है जो कि पुलिस विभाग से सेवा निवृत हैं की, सहभागिता भी रही। जयहिंद वन्देमातरम. हमारा संगठन ।

व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते है – गिरीश चंद्र यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। किराना व्यापार संघ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन शहर के मध्य स्थित एक होटल में किया गया,

मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गरीश चन्द्र यादव जी (खेल एवं युवा) उपस्थित रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता जौनपुर उद्योग व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन ने की, शिविर का मुख्य उद्देश्य व्यापारयों को विभागीय नियमों के प्रति जागरूक करना और उनकी व्यावहारिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करना था मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन मे कहा कि व्यापारी समाज अर्थव्यवस्था की रीढ़ है सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है उन्होंने व्यापारियों से अपील की वे खाद्य सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह पालन करें ताकि जनता को शुद्ध वस्तुएं मिल सकें और व्यापार में पारदर्शिता आए, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने व्यापारियों को लाइसेंशिसंग, रजिस्ट्रेशन और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी दी, शिविर के दौरान व्यापारयों ने विभाग से जुड़ी कई जटिल समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसका उन्होंने मौके पर ही उचित समाधान किया, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन ने सभी व्यापारियों से मानकों का पालन करते हुए व्यापारिक समस्याओं को व्यापार मंडल तक सूचित करने का आह्वान किया,नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने अपने उद्बोधन में किराना व्यापार संघ के पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए सभी व्यापारियों को एकजुट रहने का निवेदन किया,प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी एवं पूर्व प्रदेश पदाधिकारी आशीष गुप्ता 'आश' ने संयुक्त रूप से शिविर आयोजित करने के पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से व्यापारयों और प्रशासन के बीच की दूरी कम होती है किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रहरि ने सभी व्यापारियों का स्वागत किया,कार्यक्रम में संघ के महामंत्री आशीष कुमार गुप्ता,संरक्षक संजय केडिया,जिला संरक्षक राजदेव यादव, कोषाध्यक्ष गुलजारी लाल गुप्ता,प्रदेश युवा कोषाध्यक्ष, संतोष अग्रहरि, रामकुमार साहू, मुन्नालाल अग्रहरि, मनोज कुमार साहू, अनिल वर्मा, राजेन्दर मोदनवाल,बंटी मोदनवाल, शरद साहू, बृजेश जायसवाल, गुफरान भाई,यशवंत साहू,सिद्धनाथ शाह, मन्नू साहू,प्रवीन कुमार, अमित कुमार,गौरव मौर्य,अनुज सेठ,प्रियांशु जायसवाल,अंकित साहू, चन्दन जायसवाल, मनोज कुमार, प्रदीप साहू, रमापति केडिया, आनंद साहू,शिवम बरनवाल,संतोष जायसवाल,मनोज अग्रहरि,अभिमन्यु साहू, रामआसरे के साथ सैकड़ो की संख्या में सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जायसवाल ने किया अतिथियों का आभार संघ के महामंत्री आशीष गुप्ता ने व्यक्त किया।

नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे व पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोमवार को जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में श्मेरा गांव मेरी जिम्मेदारीश संस्था के बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक उपवास एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया। दोपहर करीब दो बजे संस्था के जिलाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, छात्रों, युवाओं और जागरूक नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने देश की शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से लाखों–करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और प्रतियोगी परीक्षाओं पर युवाओं का विश्वास कमजोर हुआ है।

ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक प्रकरण से जुड़े मानसिक तनाव के कारण जान गंवाने वाले 20 छात्रों के परिजनों को एक–एक करोड़ रुपये का मुआवजा तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई।

संस्था के जिलाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बढ़ता भ्रष्टाचार युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

समाजवादी पार्टी के नेता रत्नाकर चौबे ने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मांगों को भी सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकार किए जाने की अपील की। साथ ही, छम्म्ज पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोरतम कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

गलत जमीन पर बने मकानों के लिए भूस्वामियों को मिलेगा मुआवजा

लखनऊ, (संवाददाता)। एलडीए आईटी सिटी और वेलनेस सिटी योजना से जुड़े उन लोगों को राहत देने की तैयारी में है, जिन्हें प्रॉपर्टी डीलरों ने गलत जमीन बेच दी थी और अब उनके मकान टूटने का खतरा बना हुआ है। एलडीए ऐसे लोगों को निर्माण लागत का मुआवजा देने का प्रस्ताव बना रहा है। यह कदम योजना को कानूनी विवादों से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। एलडीए सुल्तानपुर रोड पर लैंडपूलिंग नीति के तहत आईटी और वेलनेस सिटी योजना ला रहा है। इस नीति में एलडीए भूस्वामियों से निशुल्क जमीन लेकर बदले में 25 फीसदी विकसित जमीन देता है। योजना आने से पहले ही इन गांवों में 500 से अधिक मकान बन चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मकान ग्राम समाज की जमीनों पर बने हैं। बिल्डरों ने कागज पर सही जमीन बेची, लेकिन मौके पर गलत कब्जा दिया। ये मकान 10 से 15 साल पुराने हैं और ज्यादातर बैंक कर्ज लेकर बनाए गए हैं। अब एलडीए बिना मानचित्र निर्माण का नोटिस जारी कर तोड़ने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, जिससे कानूनी अड़चनें आ रही हैं। योजना से जुड़े जानकारों के अनुसार, लैंडपूलिंग योजना में एलडीए को जमीन आने के बाद प्लॉट देना होगा।

पशुओ को खुरपका–मुँहपका रोग से बचाने के लिये चलेगा 22 जुलाई से विशेष अभियान – सीवीओ

अयोध्या। पशुधन को खुरपका–मुंहपका (एफएमडी) जैसी संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए 22 जुलाई से 08 सितम्बर तक 45 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीवीओ डॉ इंद्र देव ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के 136691 गोवंशीय और 302358 महिष वंशीय पशुओं को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे।बताया कि इसके लिए 29 टीमें गठित की गई हैं,जो रोस्टर के अनुसार गांव–गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी।उन्होंने पशुपालकों से अपील किया है कि वे सभअभियान में सहयोग करने और निर्धारित समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की अपील की गई है।बताया कि इस अभियान के तहत 136691 गोवंशीय और 302358 महिष वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा।चार माह से कम उम्र के बछड़ों तथा आठ माह से अधिक गर्भित पशुओं को इस अभियान में शामिल नहीं किया जाएगा।अभियान के सुचारु रुप से संचालन के लिए प्रत्येक विकासखंड में प्रभारी अधिकारी नामित किए गए हैं।खुरपका–मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है।इसकी चपेट में आने पर पशुओं को तेज बुखार, मुंह से अत्यधिक लार गिरना, मुंह और पैरों में छाले पड़ना, चारा छोड़ देना तथा दूध उत्पादन में भारी कमी जैसी समस्याएं होती हैं।यहाँ तक कि गंभीर स्थिति में गर्भित पशुओं का गर्भपात हो सकता है और समय पर उपचार न मिलने पर पशु की मौत भी हो सकती है। विदेशी नस्ल की गायों में इस बीमारी का खतरा अधिक रहता है।

गुड़िया निगम बनी भारतीय केसरिया वाहिनी महिला विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष

अयोध्या। लखनऊ निवासी को गुड़िया निगम को भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने महिला विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।इस मौके पर उन्होंने भारतीय केशरिया वाहिनी के महिला विभाग के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष गुडिया निगम को बधाई दिया।कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता से भारतीय केसरिया वाहिनी की विचारधारा राष्ट्रहित, सनातन संस्कृति एवं सामाजिक समरसता के संदेश के साथ जन–जन तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचेगी।कहा कि आपके नेतृत्व में महिला विभाग संगठन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई ऊँचाइयाँ प्रदान करेगी।नवनियुक्त भारतीय केसरिया वाहिनी की महिला विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड़िया निगम में भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव को आसक्त करते हुए कहा कि वह पार्टी के दायित्व को बापू भी निभाएंगे और इसके विकास में निरंतर प्रयास भी करती रहेगी।इस मौके पर नवनियुक्त भारतीय केशरिया वाहिनी महिला विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुडिया निगम का वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने बधाई दिया।

आधे घंटे की राहत फिर उमस, कीचड़ और जलभराव से फजीहत

भदोही, (संवाददाता)। जिले में चार से साढ़े चार बजे तक झमाझम बारिश हुई। ठंडी हवा चलने से लोगों को उमस से राहत मिली। बारिश रुकते ही तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और उमस से लोग बेचौन हो गए। हालांकि रात तक आसमान में बादल छाए रहे। बारिश होने से मंडलीय अस्पताल के सामने, कलेक्ट्रेट परिसर और शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। रमईपट्टी–कनौराघाट मार्ग पर पक्का पोखरा, नयेपुरवा, अघौली, अर्जुनपुर, हरिहरपुर चौराहा आदि स्थानों पर कीचड़ से पैदल चलने वालों को दिक्कत हुई। आधे घंटे की बारिश ने जलनिकासी की व्यवस्था की पोल खोल दी। मौसम विशेषज्ञ ने चार दिन तक गरज–चमक के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस था। तापमान बढ़ने और नमी अधिक होने से दिनभर उमस बनी रही। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भू–भौतिकी विभाग, बीएचयू वाराणसी ने चार दिन तक जिले में गरज–चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम को देखते हुए खेती–के कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। नोडल अधिकारी प्रो. रविशंकर सिंह एवं तकनीकी अधिकारी (मौसम वैज्ञानिक) शिव मंगल सिंह के अनुसार, इस अवधि में अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 80 से 95 प्रतिशत और न्यूनतम 53 से 82 प्रतिशत रहने की संभावना है। हवा की गति भी 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। धान के खेत में जल निकासी और मेड़बंदी मजबूत करने की सलाह दी। बारिश ने आदर्श नगर पंचायत कछवां की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी। कुछ ही देर की बारिश में कई स्थानों पर नालियां ओवरफ्लो हो गईं और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। इससे राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।` सबसे अधिक चर्चा नगर पंचायत अध्यक्ष मिताली जायसवाल के आवास के सामने की रही, जहां नाली का गंदा पानी सड़क पर बहता नजर आया।

थाने के मालखाने से ही 427 ग्राम सोना गायब

गोरखपुर, (संवाददाता)। संतकबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली के मालखाने से 427 ग्राम सोना, 49,518 रुपये और नेपाली मुद्रा गायब होने के मामले में आरोपी निलंबित दीवान राधेश्याम गुप्ता की तलाश तेज कर दी गई है। शुक्रवार सुबह संतकबीरनगर और शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने गोरखपुर के पादरी बाजार स्थित निलंबित दीवान के घर पर छापा मारा और तलाशी ली। पुलिस ने परिवार से पूछताछ भी की। हालांकि आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस टीम सुबह करीब आठ बजे सालिक रामनगर के कलेक्टरी टोला स्थित आवास पहुंची। तलाशी के दौरान घर में मौजूद दस्तावेजों की जांच की गई और परिवार के लोगों से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई गई।

सांसद रवि किशन ने दृष्टिबाधित बच्चों संग काटा जन्मदिन का केक

गोरखपुर, (संवाददाता)। सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने जन्मदिन श्रद्धा, सेवा और जनसहभागिता के साथ मनाया। जन्मदिन की शुरुआत उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन–पूजन से की। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर विधि–विधान से पूजा–अर्चना कर दृष्टिबाधित बच्चों संग केक काटा। जन्मदिन के अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी सांसद रवि किशन को शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक सहित कई केंद्र व प्रदेश स्तर के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रवि किशन शुक्ला का जन्मदिन पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, उनका उत्साहवर्धन किया तथा समाज में समावेशी सोच और सेवा भाव का संदेश दिया। इस अवसर सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के अलावा मऊ, देवरिया, आजमगढ़ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सांसद, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने सांसद रवि किशन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और निरंतर जनसेवा की कामना की।

मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के बचाव के लिए सपा नेताओं ने सौंपा ज्ञापन

अयोध्या। बीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हाजी फिरोज खान उर्फ गब्बर के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सोहावल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन देते हुए मांग की है। कहा कि मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय, रामपुर के संबंध में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय, रामपुर के संबंध में भवन निर्माण के मानचित्र (नक्शा) की स्वीकृति से जुड़े विवाद के आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। इस समाचार से विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में गहरी चिंता व्याप्त है।

विश्वविद्यालय केवल ईंट–पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह शिक्षा, ज्ञान, शोध, सामाजिक चेतना एवं राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान पर ध्वस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई का सीधा प्रभाव हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा, उनके भविष्य, रोजगार तथा शैक्षणिक वातावरण पर पड़ता है।

यदि संस्थान से संबंधित किसी प्रकार की वैधानिक, तकनीकी अथवा प्रशासनिक कमियाँ हैं, तो हमारा विनम्र अनुरोध है कि संबंधित पक्ष को कानून एवं नियमों के अनुरूप उन कमियों को दूर करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे विधिक प्रक्रिया का भी सम्मान बना रहे और विद्यार्थियों की शिक्षा भी किसी प्रकार प्रभावित न हो।कहा कि मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय, रामपुर के संबंध में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए।

यदि किसी प्रकार की वैधानिक अथवा तकनीकी कमी है, तो उसे नियमानुसार दूर करने के लिए संस्थान को पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान किया जाए।विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षाएँ एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ किसी भी परिस्थिति में बाधित न होने दी जाएँ।शिक्षा के अधिकार, विद्यार्थियों के भविष्य तथा व्यापक जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न्यायसंगत एवं संवेदनशील निर्णय लिया जाए।

प्रतिनिधिमंडल में बीकापुर विधानसभा अध्यक्ष अजय वर्मा राजू, प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार पटेल, युवजन सभा के जिलाध्यक्ष जय सिंह यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राशिद जमील, विधानसभा प्रभारी एजाज अहमद, सोहावल ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव, मसौधा ब्लॉक अध्यक्ष सूरज निषाद, अवधेश गोस्वामी, जगजीवन पटेल, दीपक यादव, सभासद अबरार अहमद, शोएब खान, शफीक अहमद, दिनेश चौधरी, दानिश खान, मसीदुल हसन खान, दया शंकर भारती, मनोज कुमार, रामकरण यादव, बुद्धिराम यादव, आमिर खान, एशात खान, दान बहादुर यादव, नफीस खान, जनक लाल वर्मा, अमरेंद्र वर्मा, निजाम खान, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हलीम उर्फ कल्लू, दयानन्द पासी, अनुभव प्रजापति, अमर रावत, राजा सिंह, मनोज पांडेय, सचिन कुमार, मोहम्मद आतिफ प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने छात्राओं को किया जागरूक

अयोध्या। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौड़ ने पीआरडी राजकुमारी के साथ अयोध्या रिकाबगंज चौराहे पर अभियान चलाकर छात्राओं को सुरक्षात्मक उपाय बताये।इस मौके पर उन्होंने वहाँ पर मौजूद छात्राओं से अपील किया कि आप सभी घर से निकलते समय हमेशा सतर्कता बरते।इस मौके पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

विधायक ने 1.11 करोड़ की लागत से दो नई सड़कों का किया शिलान्यास

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से बनने वाली दो सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं और इन परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अयोध्या में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि शहर से लेकर गांव तक हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सड़कें, बेहतर संपर्क मार्ग और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इन दोनों सड़कों के निर्माण से बड़ी संख्या लोगों को सीधा लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।शिलान्यास के दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक का स्वागत करते हुए क्षेत्र में लगातार कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया।वहीं विधायक ने जिन सड़को का शिलान्यास किया।उसमें त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत ग्राम मित्रसेनपुर में महारानी पुरवा संपर्क मार्ग तक 725 मीटर लंबी नई सड़क का निर्माण कराया जाएगा।इस परियोजना पर 42.98 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा पूर्वांचल विकास निधि से दर्शननगर वार्ड में मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर–2 के सामने से सावित्री देवी के घर होते हुए क्षितिज कौशल के गोदाम तक 450 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना की लागत 67.34 लाख रुपये निर्धारित की गई है।मौके पर गन्ना समिति के चेयरमैन दीपेन्द्र सिंह, हरभजन गौड़, स्वाति सिंह, देवता पटेल, मीडिया प्रभारी अमित मिश्र, कपिल देव वर्मा, दिनेश मिश्र, अनूप वर्मा , राजेश पाठक, वरूण चौधरी, शोभाराम वर्मा, संग्राम पटेल, पार्षद मनीष चौधरी, अरविन्द पाण्डेय, लक्ष्मण वर्मा, राम जन्म विश्वकर्मा, अभिषेक राज, अरविन्द शुक्ला, रवि तिवारी, प्रभाशंकर पाण्डेय, सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही।

बाल कल्याण समिति ने पुलिस के साथ देवकाली बाईपास स्थित आर्य स्पा सेंटर पर मारा छापा

अयोध्या। सोमवार को बाल कल्याण समिति और पुलिस ने संयुक्त रूप से देवकाली बाईपास स्थित आर्य स्पा सेंटर पर छापा मारा। छापे के दौरान औचक निरीक्षण मे स्पा सेंटर में कोई संदिग्ध गतिविधि या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।इस मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले भर में स्पा सेंटरों की जांच की जा रही है।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नाबालिग लड़कियों के शोषण की रोकथाम करना है।इस कार्यवाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि कहीं माइनर लड़कियों से अवैध कार्य तो नहीं कराया जा रहा।निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों और आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण और छापेमारी जारी रहेगी।इस मौके पर रानोपाली चौकी इंचार्ज राहुल वाजपेई सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने सौपा ज्ञापन

अयोध्या। नगर निगम में संघ का चुनाव करने को लेकर उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौपा।ज्ञापन के माध्यम से संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल समुन्दे ने मांग किया कि नगर निगम अयोध्या धाम में सफाई नायक विनय बाघमार द्वारा बिना किसी चुनाव के स्वयं घोषित अध्यक्ष मान रहा है।जो अवैध रुप से गलत है। उन्होंने विनय बाघमार पर आरोप लगाया कि वे संघ के नाम पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डराकर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सफाई कर्मियों के देय के भुगतान,मृतक आश्रित एवं सेवा निवृत कर्मचारियों के प्रकरणों में लंबा–लंबा सौदा देखकर कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं। इस मौके पर उनके अलावा संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

डीएम के सामने हुई नोकझोंक के बाद तीन अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज

अयोध्या। शनिवार को रुदौली तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की मौजूदगी में हुई तीखी नोकझोंक के मामले में नया मोड़ आ गया है।इस मामले मे लेखपाल वेद प्रकाश यादव की तहरीर पर कोतवाली रुदौली में अधिवक्ता गोरखनाथ तिवारी, रमेश शुक्ला और आशीष पांडेय के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, लोक सेवकों से अभद्रता समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध मे सीओ रुदौली अरविन्द सोनकर ने बताया कि इस मामले मे पुलिस जांच मे जुट गई है।वहीं,अधिवक्ता पक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है।

जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में सुनी 75 शिकायतें'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिलाधिकारी अनुनय झा ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में आज कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर एवं संवेदनशील मामलों का मौके पर जाकर सत्यापन कराते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

विकास वर्मा जंतर मंतर पहुंचकर संसद मार्च में भाग लिया और शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जंतर मंतर नई दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास वर्मा अपने सैकड़ो साथियों के साथ जंतर मंतर नई दिल्ली पर पहुंचकर युवा प्रदर्शनध्संसद मार्च में भाग लिया और सोनम वांगचुग तथा अभिजीत दीपके आदि द्वारा चलाए जा रहे आमरण–अनशन का समर्थन किया।विकास वर्मा ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों की लापरवाही या मिली भगत से पेपर लीक हो रहे हैं जिसके कारण छात्रों,नौजवानों का परिश्रम, धन और समय बर्बाद हो रहा है जिसके कारण नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और काफी नौजवान,छात्र हताश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों व मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। परंतु देश के शिक्षा मंत्री जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं जिनके इस्तीफा की मांग को लेकर देश का नौजवान आक्रोशित है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता,पर्यावरण विद् सोनम वांग चुक सहित तमाम नौजवान आमरण अनशन पर हैं फिर भी शिक्षा मंत्री द्वारा इस्तीफा न देना और भारत सरकार के इशारे पर दिल्ली सरकार सोनम वांगचुक सहित नौजवानों व छात्रों के साथ धक्का मुक्की, मारपीट, गाली गलौज कर रही है जिसका जवाब मजबूती से दिया जाएगा।

अतिक्रमण की गिरफ्त में नियावां मछली मंडी,जाम और अव्यवस्थाओं से परेशान राहगीर

अयोध्या। कैंट थाना क्षेत्र मे नियावां मछली मंडी इन दिनों अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं के चलते लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मंडी की दोनों पटरियों पर ठेले–खोमचे लगे होने के साथ ही एक ओर मछली बाजार संचालित हो रहा है।वहीं, मछली बाजार के सामने मछली काटने और बनाने के लिए रखी गई गुमटियां आवागमन में पूरी तरह बाधा उत्पन्न कर रही हैं। हालात यह हैं कि सड़क पर लगातार अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है।कई बार जाम को लेकर वाहन चालकों और दुकानदारों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि मामला बड़े विवाद का रूप ले लेता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाना कैंट क्षेत्र की चौकी के अंतर्गत आने वाली नियावां मछली मंडी में अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार पुलिसकर्मी इस ओर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। राहगीरों व स्थानीय लोगों का कहना है कि चौकी इंचार्ज से लेकर वहां तैनात पुलिसकर्मियों तक की नजर इस गंभीर समस्या पर नहीं पड़ रही है।पुलिस की निष्क्रियता के चलते अतिक्रमण कारियों के हौसले बुलंद हैं और राहगीरों को रोजाना जाम तथा अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।